

प्रेषक,

डा० आर. सी. श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव,
लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

लघु उद्योग अनुभाग-4
फरवरी 2008

लखनऊ : दिनांक 06

विषय: गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश लैण्डलाग्ड राज्य होने के कारण जो माल निर्यात किया जाता है वह समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की अपेक्षा मंहगा पड़ता है, इस कारण प्रदेश में दूरस्त क्षेत्रों में पारम्परिक उत्पादन कौशल होते हुये भी निर्यात का विकास वांछित स्तर का नहीं हो पाता। इसको दृष्टिगत रखते हुये शासनादेश संख्या-916/18-4-99-18(बजट-4)/99 दिनांक 14 जुलाई, 1999 तत्कम में संशोधित शासनादेश संख्या-2600/18-4-99-18(बजट-4)/99 दिनांक 24 सितम्बर, 1999 में निहित प्राविधानानुसार प्रदेश के निर्यातकों को अपने उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपो तथा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से भेजे जाने वाले माल पर हुये भाड़े की प्रतिपूर्ति हेतु एक्सपोर्ट फ्रेट प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2007-08 से उक्त शासनादेश के प्राविधानों में कतिपय संशोधनों के उपरांत त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह अनुदान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी के समस्त औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक भेजे जाने पर भाड़े में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भाड़े का 25 प्रतिशत अधिकतम रु० 5000 प्रति टी०ई०यू० (20फिट कन्टेनर) की दर से प्रदान किया जायेगा जिसकी प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा रु० 10.00 लाख तक होगी।

उपरोक्तानुसार अनुदान की धनराशि की स्वीकृति सम्बन्धित इनलैण्ड कन्टेनर डिपो तथा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन संचालित एजेन्सी की संस्तुति पर जिला यूजर्स कमेटी द्वारा की जायेगी। यूजर्स कमेटी का गठन निम्नवत् होगा :-

- | | |
|--|------------|
| 1. सम्बन्धित जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र | सदस्य-सचिव |
| 3. प्रबन्धक (निर्यात), जिला उद्योग केन्द्र | सदस्य |
| 4. जनपद के प्रमुख निर्यातक लघु उद्योग इकाईयों के तीन प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. प्रभारी इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन | सदस्य |

लघु उद्योग इकाईयों के प्रतिनिधि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगे । जिला यूजर्स कमेटी द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के माध्यम से सम्बन्धित इकाईयों को बजट की उपलब्धता के आधार पर भुगतान कराई जायेगी । इस शासनादेश के साथ योजना की मार्गदर्शिका एवं आवेदन-पत्र का प्रारूप संलग्न है ।

उपरोक्तानुसार उल्लिखित वित्तीय सहायता वर्ष 2007-08 में पात्र निर्यातकों द्वारा भेजे गये कन्टेनरों के सापेक्ष उपलब्ध कराई जायेगी तथा वर्ष 2006-07 व इसके पूर्व दावा वर्षों के अन्तर्गत भेजे गये कन्टेनरों के सापेक्ष पूर्व शासनादेश संख्या-916 दिनांक 14.7.1999 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश संख्या-2600 दिनांक 24.9.1999 में उल्लिखित दर के अनुसार वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी जिसका भुगतान इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 के आवंटित बजट से किया जायेगा ।

यह शासनादेश वित्त विभाग के अशा० सं०-ई०-६-९७८-१०-०८ दिनांक 24.1.2008 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

(डा० आर. सी. श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव,

लघु उद्योग एवं निर्यात

प्रोत्साहन,

उ०प्र० शासन ।

शासनादेश संख्या 668 (1)/18-4-2008-10(बजट)/2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम/उ०प्र० राज्य भण्डारण निगम/कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
3. परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश ।
5. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी ।
6. अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ०प्र० शासन ।

आज्ञा से,

(मारकण्डेय सिंह)

विशेष सचिव

गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान

मार्गदर्शिका निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उत्तर प्रदेश सरकार

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यातकों को राज्य के भू-आच्छादित होने के कारण अपने उत्पादों को गेटवे पोर्ट तक परिवहन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के भार को कम करते हुये निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान योजना के संचालन का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता की रूपरेखा निम्नवत् है:-

प्रस्तावना :- इस योजना को "गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान" के नाम से जाना जायेगा। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र की निर्यातक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक भेजे जाने हेतु भाड़े में किये गये व्यय में कमी करते हुये बन्दरगाहों के समीप स्थित राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त व्यय-भार की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

परिभाषायें :-

1. राज्य का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश" राज्य से है।
2. **एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो**- इसका तात्पर्य प्रदेश से निर्यात के प्रोत्साहन हेतु गठित किये गये ब्यूरो से है।
3. निर्यातक से तात्पर्य उत्तर प्रदेश के अन्दर कार्यरत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादक-निर्यातक से है, जिसका उत्पादन केन्द्र उ०प्र० में हो तथा उद्योग निदेशालय उ०प्र० के अधीनस्थ सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत हो अथवा और 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006' के धारा-8 के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के रूप में सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में ज्ञापन जमा किया हो तथा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो से उत्पादक-निर्यातक के रूप में पंजीकृत हो।
4. आई०सी०डी०/सी०एफ०एस०-इसका तात्पर्य इनलैण्ड कन्टेनर डिपो तथा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के उन केन्द्रों से है जो उ०प्र० में स्थित हों।

अतिरिक्त व्यय-भार की प्रतिपूर्ति योजना के लिए पात्रता :- इस वित्तीय सहायता की अनुमन्यता के लिए निम्नलिखित शर्तें होगी:-

1. निर्यातक जिसका उत्पादन केन्द्र उ०प्र० में हो तथा उद्योग निदेशालय उ०प्र० के अधीनस्थ सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत हो अथवा और 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006' के धारा-8 के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के रूप में सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में ज्ञापन जमा किया हो तथा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो से उत्पादक-निर्यातक के रूप में पंजीकृत हो।
2. निर्यातक के पास ज्वाइण्ट डी०जी०एफ०टी० के कार्यालय/कार्यालयों से प्राप्त आई०ई०कोड पंजीकरण संख्या हो।

अतिरिक्त व्यय-भार प्रतिपूर्ति की राशि :-

1. यह धनराशि आई0सी0डी0/सी0एफ0एस0 द्वारा निर्यात हेतु भेजे गये माल पर परिवहन मद में होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत अथवा रू0 5000/- प्रति टी0ई0यू0, जो भी कम हो, अनुमन्य होगी जो निर्यातकों द्वारा निर्यात हेतु दिनांक 1. 4.2007 के पश्चात् भेजे गये माल पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु लागू होगी ।
2. वित्तीय वर्ष 2006-07 व इसके पूर्व दावा वर्षों के अन्तर्गत भेजे गये कन्टेनरों के सापेक्ष पूर्व शासनादेश संख्या-916 दिनांक 14.7.1999 एवं तत्कम में संशोधित शासनादेश संख्या-2600 दिनांक 24.9.1999 में उल्लिखित दर के अनुसार वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी जिसका भुगतान इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 के आवंटित बजट से किया जायेगा।

विशेष :-

1. इस वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद अथवा योजना के संचालन के सम्बन्ध में निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन द्वारा दिया जाने वाला निर्णय अन्तिम होगा।
2. योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्र एवं आई0सी0डी0/सी0एफ0एस0 के प्रभारी के स्तर से दी जाने वाली सत्यापन रिपोर्ट का प्रारूप एवं संलग्न है।

भवदीय,

(डा0 आर. सी. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
लघु उद्योग एवं निर्यात
प्रोत्साहन,
उ0प्र0 शासन।

गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान
के दावे का आवेदन-पत्र

1. फर्म का नाम :
2. पूरा पता :
3. ई0पी0बी0 पंजीयन संख्या एवं दिनांक :
4. सूक्ष्म/लघु उद्योग पंजीयन/ज्ञापन संख्या एवं दिनांक :
5. प्रबन्ध निदेशक/पार्टनर/प्रोप्राईटर का नाम :
6. दूरभाष/फैक्स/ई-मेल/इण्टरनेट आदि का विवरण :
7. निर्यातक की श्रेणी (सूक्ष्म/लघु उद्योग) :
8. आयात-निर्यात कोड नं0 तथा जारी करने वाले
डी0जी0एफ0टी0 कार्यालय का पता :
9. आई0सी0डी0/सी0एफ0एस0 के माध्यम से निर्यात हेतु
भेजे गये कन्टेनर्स का विवरण :
- अ. निर्यात की तिथि :
- ब. कन्टेनर सं० :
- स. कन्टेनर की माप (20फिट/40फिट) :
- द. निर्यात की जाने वाली वस्तु का विवरण :
- य. आयातक देश का नाम :
- र. परिवहन शुल्क :
- ल. कैश रसीद नं० :

आवेदक के हस्ताक्षर

आई०सी०डी० अधिकारी की रिपोर्ट :-

प्रार्थना-पत्र के क्रम सं०.....पर उपलब्ध विवरणों का परीक्षण सी०एफ०एस०/आई०सी०डी० में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कर लिया गया है तथा त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान हेतु अनुमन्य पाया गया है। इस सम्बन्ध में आई०सी०डी०/सी०एफ०एस० के स्तर की सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं।

प्रबन्धक
(आई०सी०डी०/सी०एफ०एस०)
लेखाकार/खजांची।